



भारत में उच्च शिक्षा तथा उसकी समस्याएँ

शोभना त्रिपाठी

प्रवक्ता,

अग्रसेन महाविद्यालय, बरेली।

(उत्तर प्रदेश)

यदि हम उच्च का शाब्दिक अर्थ लें तो देखेंगे सर्वश्रेष्ठ या ऊँचा। यदि इसे शिक्षा के अर्थ में लिया जाये तो देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद प्रारम्भ होने वाली शिक्षा। आधुनिक भारत में दिखायी देने वाली उच्च शिक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों की देन है।

“There is a general feeling in India that the situation in higher education is unsatisfactory and even alarming.”

-Kothari Commission Report

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उसका संख्यात्मक विकास अत्यन्त त्वरित गति से हुआ है। परन्तु वर्तमान में शिक्षा का स्तर गिर गया है। छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट हो गयी है। शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या आ गयी है। वर्तमान शिक्षा भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गयी है।

कोठारी कमीशन में लिखा है – “भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असन्तोषजनक एवं भयप्रद भी है।” इसका कारण है उसमें व्याप्त अनेक समस्याएँ व्याप्त हैं जिनमें हैं –

1. छात्रों के प्रवेश की समस्या – शिक्षा संस्थाओं में छात्र तथा छात्राओं के प्रवेश की एक बड़ी समस्या है। जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। जब छात्रों या छात्राओं को मन के महाविद्यालय में प्रवेश नहीं

मिलता है तो वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारी शिक्षा कालक्ष्य ज्ञान देना होना चाहिए न कि कक्षाएँ पास करना। मन की शिक्षा न मिलने से शिक्षार्थियों को ऊब होती है तथा वे केवल कक्षा पास कर लेते हैं।

समाधान : यूँ तो सरकार की तरफ से सभी को उच्च शिक्षित करने के लिए स्ववित्तपाषित निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं को मान्यता मिल रही है परन्तु उसमें नियमों का पालन होना आवश्यक है तथा उनके शुल्कों पर भी नियंत्रण होना चाहिए।

“यूँ तो उच्च शिक्षा का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व तो होता ही है और होना भी चाहिए आवश्यकता है व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को बढ़ाने की। और यह भी सम्भव है जब व्यावसायिक एवं तकनीकी की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को ही सक्षम किया जाये।”¹

यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर लें तो शिक्षार्थियों की संख्या कम रहेगी तथा उन्हें अपने मन के महाविद्यालयों में प्रवेश मिल सकेगा।

यदि चयन प्रक्रिया में पूर्व परीक्षा तथा प्रवेश परीक्षा को बराबर (50 प्रतिशत) महत्व दिया जाये तो छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकते हैं।

सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है जिसने शिक्षा के क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है। यदि उसे किसी प्रकार कम किया जा सक तो शायद उच्च शिक्षा में प्रतिभावान शिक्षार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। परन्तु इसके लिए एक बड़ी क्रान्ति की आवश्यकता होगी।

दूसरी समस्या उद्देश्यहीनता की है।

2. उद्देश्यहीनता : उच्च शिक्षा की उद्देश्यहीनता तो सर्वविदित है ही। समय तथा देश की परिस्थितियाँ दोनों ही बदल गये हैं। परन्तु जिस प्रकार उच्च शिक्षा परतन्त्र भारत में व्यक्ति को जीवन के लिये तैयार नहीं करती थी ठीक उसी प्रकार यह स्वतन्त्र

भारत में भी तैयार नहीं करती। हुमायूँ कबीर ने बताया है “बहुत वार यह कहा गया है कि वि”वविद्यालय में जो िक्षा दी जाती है वह व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के लिये तैयार नहीं करती है।”²

हमारे वि”वविद्यालयों की उद्दे”यहीन िक्षा और हमारे दे”ा एवं नवयुवकों के जीवन पर कुठाराघात कर रही है।

समाधान : “हमारे दे”ा के वि”वविद्यालयों की उद्दे”यहीन िक्षा ने दे”ा और नागरिकों को विकारयुक्त कर दिया है कि इस दि”ा में वांछनीय एवं उपयुक्त उद्दे”य शीघ्र निर्धारित किये जायें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्र की सम्पन्नता तथा निवासियों के कल्याण की बातें करना गल्प संग्रह हो जायेगा।”³

यद्यपि समय-समय पर हमारे आयोग िक्षा के उद्दे”य निर्धारित करते आये हैं। यदि सभी कमी”ानों के द्वारा निर्धारित उद्दे”यों को देखें तो हमें शब्दावली में अन्तर मिलेगा, परन्तु सार में नहीं।

भारतीय वि”वविद्यालय मानवता तथा सहिष्णुता की िक्षा दें। वे नवीन विचारों तथा सत्य की खोज के लिये प्रेरित करें। राष्ट्र को स”ाक्त एवं प्रगति”ील बनाने का प्रयास करें। जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है –

“यदि वि”वविद्यालय अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करें तो राष्ट्र एवं जनता का कल्याण हो सकता है।”

तीसरी बड़ी समस्या

3. शिक्षा के निजीकरण की समस्या : भारत में िक्षा के निजीकरण से सुविधा भी है परन्तु वह एक समस्या के रूप में भी देखा जाता है। िक्षा समवर्ती सूची में है तथा इसकी व्यवस्था केन्द्र तथा प्रान्त सरकारों द्वारा की जाती है। मार्च 2003 में जब विद्यार्थी परिषद ने स्ववित्त पोषित उच्च िक्षा संस्थाओं को मान्यता देने और उच्च

शिक्षा का निजीकरण करने के विरोध में संसद के सामने प्रदर्शन किया तो मानव संसाधन मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने आवासन दिया कि सरकार उच्च शिक्षा निजीकरण को कोई इरादा नहीं रखती है।

इन निजीकरण संस्थाओं में शुल्क मनमाना वसूला जाता है। सरकार इसमें कोई रूचि नहीं ले रही है। फलतः ये संस्थाएँ मनमाना शुल्क बढ़ा देती हैं। इनकी मानक पूरी नहीं होती है, इन्हें पैसों से मान्यता मिल रही है अधिकांश संस्थाएँ तो धन कमाने की संस्था बनी हैं।

“स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक तथा शैक्षिक शोषण सर्वत्र ज्ञात है।”⁴ उच्च शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र के विभिन्न कार्य के लिये विषयों का निर्माण करना है।

सरकार स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे के द्वारा शिक्षार्थियों के प्रवेश नियमों को निर्धारित कर सकती है। मान्यता देने के लिए सिफारिश या धन नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिये ईमानदार होना आवश्यक है। नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करवाना अनिवार्य है।

अन्य समस्या हैं –

4. पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना : स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का प्रसार इतना हुआ है कि सभी सीमाएं पार हो गयी हैं। शिक्षा प्रसार का नाम लेकर थोड़ी सी भूमि में कुछ कमरे खड़े करके उन्हें कालेजों की संज्ञा दी गयी है। यह सब मात्र धन कमाने के लिये किया जाता है। इन संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रम ठीक नहीं है। इनमें कठोरता है, विविधता नहीं है, व्यावसायिक विषयों का अभाव है, शिक्षार्थियों को समाजोपयोगी पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। शिक्षार्थी रूचि के अनुसार पाठ चयन नहीं कर सकते। अतः उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यद्यपि आज के भारत की आवश्यकताएँ

पराधीन भारत से अलग हैं परन्तु पाठ्यक्रम में अन्तर दिख नहीं रहा है। वही धिसे-पिटे विषय हैं जो पहले थे।

राधाकृष्णन् कमीशन में लिखा है – “जो पाठ्यक्रम वैदिक काल में उपयोगी था उसे 20वीं शताब्दी में बिना परिवर्तन किये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।”

समाधान : पाठ्यक्रम में कठोरता उचित नहीं है। लचीला पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्नातक स्तर पर सामान्य विधि तथा आर्नस पाठ्यक्रम होने चाहिए।

“पाठ्यक्रम का देना एवं व्यक्तियों की आवश्यकताओं से सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव हो, व्यावसायिक विषयों और कृषि विज्ञान प्राविधिक शिक्षा को स्थान दिया जाये।”⁵

5. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली

हमारी परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है जिसका कारण है यह निबन्धात्मक है। जोकि सम्पूर्ण पाठ्यविषयों पर आधारित नहीं है। यह एक अंश पर आधारित होती है। इस परीक्षा प्रणाली में आन्तरिक परीक्षाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यह समस्या आज से नहीं एक शताब्दी से विद्यमान है। इस परीक्षा में छात्र सालभर न पढ़कर परीक्षा के दिनों में ही पढ़ना चाहता है जिससे वह कुछ अंश ही पढ़ लेता है। 1902 में भारतीय विवेकविद्यालय आयोग ने कहा है – “भारत में विवेकविद्यालय शिक्षा का महानतम दोष यह है कि शिक्षण परीक्षा के अधीन है न कि परीक्षा शिक्षण के।” इस परीक्षा में छात्र पढ़ाई के प्रति उदासीन होते हैं वे प्रश्न का उत्तर कभी-कभी उचित रूप से नहीं देते हैं तथा गहराई से ज्ञान प्राप्त करने पर विवास नहीं करते हैं। डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं बस।

समाधान : इसके समाधान के लिए प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित सम्पूर्ण अंकों में से एक तिहाई अंक कक्षा कार्य के लिये हों। प्रत्येक वि"विद्यालय में परीक्षकों का एक स्थायी बोर्ड होना चाहिए जिसे वि"विद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की योजनाएँ बनाने में सहायता देनी चाहिए।

वि"विद्यालयों में वाह्य परीक्षाओं का स्थान शिक्षकों के आन्तरिक मूल्यांकन को दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को मूल्यांकन की नवीन एवं उन्नत विधियों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिये प्रगति परीक्षाओं को आरम्भ किया जाये। विचार गोष्ठियों तथा ट्यूटोरियल कार्य भी प्रयोग में लाये जायें।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में बताया "परीक्षा सुधार का कार्यक्रम जो वि"विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है, पाँचवीं योजना में तेजी से किया जायेगा।"

परीक्षा सुधार लम्बे समय से चर्चा का विषय रहा है। प्रामाणिक एवं वि"वसनीय मानदण्ड तैयार करके अध्ययन तथा अध्यापन को स"िक्त बनाया जा सकता है।

6. उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने की समस्या

"हमारे दे"ा में आज पढ़ने तथा पढ़ाने का माहौल ही नहीं रह गया है। शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लते। छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते।"⁶ उच्च शिक्षा में नकल आम बात हो गयी है। नकल की आस में शिक्षार्थियों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। जो भी शोध कार्य किये जा रहे हैं उनका उद्दे"य केवल उपाधि प्राप्त करना ही है। आज की राजनीति ने शिक्षण संस्थाओं को भी अछूता नहीं छोड़ा है। राजनैतिक गतिविधियों के कारण महाविद्यालयों में अनु"ासनहीनता लगातार बढ़ रही है। छात्र भी सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं तथा वह उसके अपने कैरियर के रूप में देखने लगते हैं। जिससे वे छात्र कम नेता अधिक हो जाते हैं। आयेदिन कक्षाओं का वहिष्कार कर अन्य छात्रों को भी इसके लिए उकसाते रहते हैं जिससे शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है।

समस्या : सुधार के उचित उपाय अपनाकर बदलाव लाया जा सकता है। जैसे सरकार उच्च शिक्षा पर पर्याप्त धनराशि व्यय करे, विविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को इसके लिये बढ़-चढ़कर काम करना चाहिए। शोधकार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। शिक्षार्थियों की प्रतिभात उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाये। अभिभावकों को सचेत करना सबसे आवश्यक है।

7. शिक्षा में विशिष्टीकरण की समस्या

विविद्यालय स्तर पर शिक्षा में विशिष्टीकरण प्रारम्भ हो जाता है। छात्र विभिन्न विषयों का विशेष अध्ययन कर सकते हैं इस प्रकार के अध्ययन से उन्हें विशेष विषयों में दक्षता मिलती है। परन्तु इस अध्ययन से उनका दृष्टिकोण असन्तुलित एवं अव्यवहारिक हो जाता है।

के.जी.सैयदन ने लिखा है – “विशिष्टीकरण में एक प्रकार की संकीर्णता एवं अकाल्पनिकता होती है।”

समाधान : इसके समाधान के लिये छात्र जो ज्ञान अर्जित करते हैं उनमें सामंजस्य एवं अन्तर्सम्बन्ध होना चाहिए। जब तक सामंजस्य नहीं होगा मानसिक शक्तियों का विकास भी नहीं होगा। अतः विविद्यालय में सामान्य शिक्षा को महत्व दिया जाये।

विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भारतीय संस्कृति का ज्ञान सभी छात्रों को लाभान्वित करता है जिसमें साहित्य के छात्रों को विज्ञान का, विज्ञान के छात्रों को इतिहास आदि का ज्ञान हो जाता है। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होगा।

इस प्रकार उच्च शिक्षा हमारे भविष्य निर्माण की अन्तिम तथा महत्वपूर्ण सीढ़ी है जिसे पार करने के लिये हमें ईमानदारी, मेहनत, लगन तथा जागरूक होने की आवश्यकता है। यह शिक्षा देना के विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बिहारी, रमन, कृष्णकान्त (2012) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आरणलाल बुक डिपो, मेरठ। पृष्ठ सं. 439
2. कबीर हुमायूँ स्वतंत्र भारत में शिक्षा। पृ.सं. 135
3. पाठक, पी.डी. (2015) भारतीय शिक्षा तथा उसकी समस्याएँ। अग्रवाल पब्लिके"न्स, आगरा। पृ.सं. 312
4. सिंह बी.बी. (2013) आहूजा सुधाभारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास। आर. लाल बुक डिपो, आगरा। पृ.सं. 318
5. पाठक, पी.डी. (2015) भारतीय शिक्षा तथा उसकी समस्याएँ। अग्रवाल पब्लिके"न्स, आगरा। पृ.सं. 313
6. बिहारी, रमन, कृष्णकान्त (2012) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आरणलाल बुक डिपो, मेरठ। पृष्ठ सं. 440